

नवनियुक्त जजों का ओवेशन कार्यक्रम आज

बिलासपुर 26 जून। छग हाईकोर्ट के नवनियुक्त तीन जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल जस्टिस रामप्रसन्न शर्मा, और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता, का ओवेशन मंगलवार को चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में सुबह 10.30 बजे होगा।

हाईकोर्ट में अरविंद सिंह चंदेल, रामप्रसन्न शर्मा और शरद कुमार गुप्ता के छग हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्युडिशियल गौतम चौरड़िया ने तीनों जजों के ओवेशन की तिथि तय कर दी है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौरड़िया की अधिसूचना के अनुसार जस्टिस अरविंद चंदेल, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता और जस्टिस राम प्रसन्न शर्मा का ओवेशन कार्यक्रम 27 जून को सुबह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन के कोर्ट रूम में होगा। ओवेशन

कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस सहित रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में तीनों जस्टिस के परिजन भी शामिल होंगे। इनके बैठने की भी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए इन तीनों जजों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 14 हो जाएगी। अभी वर्तमान में जजों की संख्या 11 है।

गौतम चौरड़िया भी करेंगे

पदभार ग्रहण

छग हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद सिंह चंदेल का हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के बाद रिक्त हुए रजिस्ट्रार जनरल के पद पर गौतम चौरड़िया को नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल भी मंगलवार को पदभार ग्रहण करेंगे।

रसोई गैस सिलेण्डर चोरी

बिलासपुर, 26 जून। कोतवाली थाना क्षेत्र के आरके गली में बीती रात चोरी ने एक मकान से गैस सिलेण्डर की टंकी चोरी कर फरा हो गये। जब घटना हुई महिला घर में सो रही थी। सुदेवी कश्यप ने पुलिस को बयान में बताया कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है। जिसके चलते उसने बास और टूटे का दरवाजा बनाया था उसे किसी ने तोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 26 जून। नगर निगम की उचित मूल्य दुकानों में एक जुलाई 2017 से कोर पीडीएस पर 'भेरी मर्जी' योजना लागू होगी। इसके बाद हितग्राही किसी भी राशन से अपना खाद्यान्न उठा सकेंगे। इसके लिए राशन दुकान संचालकों को प्रशिक्षण भी शनिवार को दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान खाद्य विभाग के संचालक डी.सिंह उपस्थित थे। शहर में एक जुलाई से राशन का वितरण ऑनलाईन होगा। ऑफ लाईन वितरण बंद कर दिया जाएगा। शहर के 66 वार्डों के 100 दुकानों में कोर पीडीएस लागू हो जाएगी। अभी तक बिलासपुर शहर के राशन कार्डधारी अपने मूल दुकान से राशन लेने बाध्य थे लेकिन अब इसकी बाध्दता नहीं है। इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलेगा तो खाद्य विभाग के अमले पर कार्रवाई होगी। दुकान संचालक की जिम्मेदारी है कि वे जीपीआरएस या मोबाईल की बेहतर कनेक्टिविटी वाली सर्विस लें। नगर निगम क्षेत्र में किसी भी दुकान में नेटवर्क की समस्या न हो। जहां कनेक्टिविटी की समस्या हो ऐसी जगहों पर दुकान संचालित न करें। सामग्री की नुट्रिटरिह एन्ट्री टेबलेट में की जाए। टेबलेट व ब्यायोमेट्रिक्स डिवाइस का कनेक्टर अच्छी कंपनी का हो और इन उपकरणों का उचित रख-रखाव करें। उन्होंने दुकानदारों से स्पष्ट कहा कि किसी भी हितग्राही को आधार प्रमाणीकरण के अभाव में राशन देने से मना नहीं करना है। उनका फोटो लेकर उन्हें राशन सामग्री दी जाए



तथा आधार प्रमाणीकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जिन हितग्राहियों का आधार नंबर नहीं लिया गया है उनसे आधार नंबर लें। भारत सरकार ने 30 जून तक इसकी समयसीमा रखी है। अपर संचालक राजीव जायसवाल ने कहा कि दुकान संचालक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करें। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। खाद्य विभाग व नान की जिम्मेदारी होगी कि वे बिलासपुर शहर में 3-4 चलित उचित मूल्य दुकान संचालित करें। जहां पर टेबलेट काम नहीं करेगा, उन दुकानों में चलित वाहन से राशन सामग्री प्रदान करें। कोर पीडीएस में क्या सुविधा है इस बारे में सभी राशन दुकानों में सूचना चस्पा करें। हर उपभोक्ता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिन शहरों में कोर पीडीएस व्यवस्था चालू है उनमें से किसी भी शहर में हितग्राही राशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को शहरी क्षेत्र के दुकानों से राशन नहीं मिलेगा।

खाद्य संचालनालय के प्रोग्रामर मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोर पीडीएस से संबंधित प्रशिक्षण दिया। एप्लीकेशन क्या है, यह कैसे काम करेगा, आधार प्रमाणीकरण कैसे करेगे, प्रमाणीकरण के समय किन बातों का ध्यान रखना है उन्होंने बताया।

इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर के.डी. कुंजाम, खाद्य नियंत्रक आशुतोष चतुर्वेदी सहित खाद्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान संचालक उपस्थित थे।



डोंगरगढ़। स्थानीय गोलबाजार स्थित मस्जिद में क्षेत्रीय विधायक सरोजनी बंजारे, मंडल अध्यक्ष अमीत जैन, जीवन् बंजारे, महामंत्री विजेंद्र ठाकुर, बृजलाल नामदेव, अर्चला ठाकुर ने यहां ईद के मौके पर मुस्लिम भाईयों को पर्व की बधाई दी।

मंदिर ट्रस्ट ने किया खालसा को सम्मानित

छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़, 26 जून। डॉ. जे एस खालसा को बेस्ट आई सर्जन पुरस्कार मिलने पर मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों व ट्रस्टियों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उन्हें शाल-श्रीफल से सम्मानित किया।

गत दिनों नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. खालसा को राज्य सरकार ने बेस्ट आई सर्जन के खिताब से सम्मानित किया है। बताया जा रहा है कि छग सरकार द्वारा धमतरी के नेत्र विशेषज्ञ जे एस खालसा को यह पुरस्कार 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के मध्य उनके द्वारा छ ग में सबसे अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने पर प्रदान किया है। इस अवधि में डॉ. खालसा ने 2865 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन किया, जिसमें लगभग 500 ऑपरेशन मां

बन्धेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर किया। ज्ञात हो कि वर्ष 2010 से डॉ. खालसा निरंतर मंदिर चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें माह में दो बार निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाता है। आज मंदिर चिकित्सालय में 41 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। डॉ. खालसा को बेस्ट आई सर्जन पुरस्कार मिलने पर मंदिर ट्रस्ट समिति के

पदाधिकारियों व समस्त ट्रस्टियों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उन्हें शाल-श्रीफल से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष सी पी मिश्रा, कोषाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, मंत्री महेंद्र परिहार, सजीव गोमास्ता, के के तिवारी सहित नेत्र सहायक निरधर पटेल आदि कर्मचारी उपस्थित थे।



राशन दुकान संचालकों को प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 26 जून। नगर निगम की उचित मूल्य दुकानों में एक जुलाई 2017 से कोर पीडीएस पर 'भेरी मर्जी' योजना लागू होगी। इसके बाद हितग्राही किसी भी राशन से अपना खाद्यान्न उठा सकेंगे। इसके लिए राशन दुकान संचालकों को प्रशिक्षण भी शनिवार को दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान खाद्य विभाग के संचालक डी.सिंह उपस्थित थे। शहर में एक जुलाई से राशन का वितरण ऑनलाईन होगा। ऑफ लाईन वितरण बंद कर दिया जाएगा। शहर के 66 वार्डों के 100 दुकानों में कोर पीडीएस लागू हो जाएगी। अभी तक बिलासपुर शहर के राशन कार्डधारी अपने मूल दुकान से राशन लेने बाध्य थे लेकिन अब इसकी बाध्दता नहीं है। इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलेगा तो खाद्य विभाग के अमले पर कार्रवाई होगी। दुकान संचालक की जिम्मेदारी है कि वे जीपीआरएस या मोबाईल की बेहतर कनेक्टिविटी वाली सर्विस लें। नगर निगम क्षेत्र में किसी भी दुकान में नेटवर्क की समस्या न हो। जहां कनेक्टिविटी की समस्या हो ऐसी जगहों पर दुकान संचालित न करें। सामग्री की नुट्रिटरिह एन्ट्री टेबलेट में की जाए। टेबलेट व ब्यायोमेट्रिक्स डिवाइस का कनेक्टर अच्छी कंपनी का हो और इन उपकरणों का उचित रख-रखाव करें। उन्होंने दुकानदारों से स्पष्ट कहा कि किसी भी हितग्राही को आधार प्रमाणीकरण के अभाव में राशन देने से मना नहीं करना है। उनका फोटो लेकर उन्हें राशन सामग्री दी जाए



तथा आधार प्रमाणीकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जिन हितग्राहियों का आधार नंबर नहीं लिया गया है उनसे आधार नंबर लें। भारत सरकार ने 30 जून तक इसकी समयसीमा रखी है। अपर संचालक राजीव जायसवाल ने कहा कि दुकान संचालक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करें। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। खाद्य विभाग व नान की जिम्मेदारी होगी कि वे बिलासपुर शहर में 3-4 चलित उचित मूल्य दुकान संचालित करें। जहां पर टेबलेट काम नहीं करेगा, उन दुकानों में चलित वाहन से राशन सामग्री प्रदान करें। कोर पीडीएस में क्या सुविधा है इस बारे में सभी राशन दुकानों में सूचना चस्पा करें। हर उपभोक्ता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिन शहरों में कोर पीडीएस व्यवस्था चालू है उनमें से किसी भी शहर में हितग्राही राशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को शहरी क्षेत्र के दुकानों से राशन नहीं मिलेगा।

खाद्य संचालनालय के प्रोग्रामर मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोर पीडीएस से संबंधित प्रशिक्षण दिया। एप्लीकेशन क्या है, यह कैसे काम करेगा, आधार प्रमाणीकरण कैसे करेगे, प्रमाणीकरण के समय किन बातों का ध्यान रखना है उन्होंने बताया।

इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर के.डी. कुंजाम, खाद्य नियंत्रक आशुतोष चतुर्वेदी सहित खाद्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान संचालक उपस्थित थे।

गलत ऑपरेशन, डॉक्टर पर 12 लाख जुर्माना

बिलासपुर, 26 जून। जिला उपभोक्ता फोरम ने गर्भाशय का गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के ऊपर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा की हेनाथ शर्मा की दायर परिवाद मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने डा अनिता गोयनका के खिलाफ निर्णय देते हुए उपचार का खर्च 2 लाख और मानसिक क्षतिपूर्ति 10 लाख और परिवाद व्यय 5 हजार देने का आदेश पारित किया है। ज्ञात हो चकरभाटा के ग्राम परसदा निवासी हेनाथ शर्मा पत्नी ममता शर्मा के पेट में दर्द हुआ। हेनाथ ने अपनी पत्नी का 1 जून 2012 में तेलीपारा स्थित शिवांगी अस्पताल में डा. अनिता गोयनका से चेकअप कराया और सोनोग्राफी और पैथोलॉजी टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉ. गोयनका ने ममता शर्मा के बच्चेदानी में सूजन आने की बात कहते हुए ऑपरेशन करने की बात कही। हेनाथ ने 2 जून को अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कर दिया।

3 जून को डॉ. गोयनका ने ममता को ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ममता की हालत में सुधार नहीं हुआ और तत्पश्चात खराब होने लगी, तब डॉक्टर ने उसे अपोलो ले जाने की सलाह दी। ममता को उसके पति हेनाथ ने अपोलो में भर्ती कराया। तीन दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अपोलो के डॉक्टरों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि बच्चेदानी में मामूली सूजन था तथा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। जल्लबाजी और गलत ऑपरेशन के कारण ममता को सेप्टेसेमिया, सेप्सिस और साइनस टेंकिकाडिया हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हेनाथ ने डॉ. गोयनका के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था।

राशन के लिए 36 किमी सफर

(पेज 13 से आगे)

के लिए मौलों चलना पड़ता है। वहाँ कुल्हाड़ीघाट के आश्रित ग्राम मटाल, कुरवापानी, ताराझर के कमार राशन प्राप्त करने कुल्हाड़ीघाट जाते हैं। कुल्हाड़ीघाट से ग्राम ताराझर की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक है। इन ग्रामों तक केवल पदयात्रा कर ही पहुँचा जा सकता है।

नहीं पहुँच पाती शासकीय योजनाएं

सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना के लिए चिन्हित ग्राम पंचायत कुल्हाड़ीघाट के पहाड़ी पर स्थित ग्राम ताराझर, मटाल, कुरवापानी व फरसरा पंचायत के आश्रित ग्राम डडईपानी तक शासकीय योजनाएं पहुँचने से पहले दम तोड़ देती हैं। इन ग्रामों में लोग नदी और झरिया का पानी का उपयोग पेंयजल के लिए करते हैं, क्योंकि इन ग्रामों में हैंडपंप तक की व्यवस्था नहीं है।

कमार जनजाति विलुप्त हो रही जनजातियों की श्रेणी में आता है। इनके विकास के लिए वर्षों से कमार विकास अभिकरण संचालित है। जिनका कार्य इस जनजातीय समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य व उन्हें आर्थिक कार्यक्रम व योजना बनाकर स्वावलंबी बनाने का है किन्तु विकास अभिकरण का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता।

मरीजों को खाट से पहुँचते हैं अस्पताल

सांसद आदर्श ग्राम पंचायत कुल्हाड़ीघाट के आश्रित ग्राम मटाल, कुरवापानी, ताराझर व फरसरा पंचायत के आश्रित ग्राम डडईपानी के ग्रामीण सड़क के अभाव में मरीजों को खाट से पंचायत मुख्यालय तक लाते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के चलते 108, महतारी एक्सप्रेस का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। ग्रामीण अपने निजी व्यवस्था से सरकारी अस्पताल विकासखंड मुख्यालय मैंनपुर तक पहुँचते हैं।



ग्राम मटाल, कुरवापानी, ताराझर व फरसरा ग्राम पंचायत के डडईपानी के लोग नदी व कुएं का पानी पीते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में आयरन रहता है। इसके चलते उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोरवेल की गाड़ियां नहीं पहुँच पाने के कारण इन जल श्रोतों का उपयोग करना उनकी मजबूरी है।

हालांकि शासन द्वारा कुल्हाड़ीघाट में जनस्वास्थ्य रक्षक नियुक्त गया है किन्तु जनस्वास्थ्य रक्षक मुख्यालय कुल्हाड़ीघाट को छोड़कर मैंनपुर में निवास करते हैं।

वनोपज से चलाते हैं परिवार का खर्च

कुल्हाड़ीघाट इलाके के पहाड़ी पर बसे ग्राम ताराझर, मटाल, कुरवापानी व फरसरा पंचायत के आश्रित ग्राम डडईपानी के लोगों के आजीविका का प्रमुख संसाधन तेन्दूपत्ता, महुआ, सालबोज का संग्रहण है। इसे बेचकर वे अपना खर्च चलाते हैं। वहाँ वे अपने परम्परागत बास बर्तन बनाने का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार

भिलाई, जिला-दुर्ग

मामला क्रमांक / / 31/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनाता फाटल आ. सुदृष्टकृष्ण पाटिल साकिन मरारपावा बोरोसी, तह. बेरला, जि. बेरसरा के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरुद प.ह.न कु/14/19 रा.नि.म.दुर्ग-1 तह.व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1572/222 का टु. रकबा 800 वर्गफीट-74.34 वर्ग मी. (0.006 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सुभाष चंद्र खत्री आ. शांकरकिरण खत्री निवासी शांति नगर, सुपौला, भिलाई, के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

अति.तहसीलदार

भिलाईनगर जिला-दुर्ग

(मुहर)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार

भिलाई, जिला-दुर्ग

मामला क्रमांक / / 31/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुर्सीवार भिलाई तह. व. जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरुद प.ह.न 14/19 रा.नि.म.दुर्ग-1 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1603/58 रकबा 2000 वर्गफीट-185.87 वर्ग मी. (0.02 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता देवेन्द्रनाथ मिश्रा आ. रघुनाथ मिश्रा निवासी 115/7 जौ. टी. रोड बाली, हवाडी (प.बंगाल) के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

अति.तहसीलदार

भिलाईनगर जिला-दुर्ग

(मुहर)

शिक्षा में भारतीय पद्धति को अपनाना चाहिए- अग्निहोत्री

बीयू के छठवें स्थापना दिवस पर नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी



छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर 26 जून। बिलासपुर विश्वविद्यालय ने छठवां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर नई शिक्षा नीति और फंडिंग पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विवि के कुलपति प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री थे। यूजीसी भोपाल

अंचल के डिप्टी डायरेक्टर एसएस बघेल, गुरुघासीदास केन्द्रीय विवि के कुलपति प्रो अंजिला गुप्ता, सुंदर लाल शर्मा मुक्त विवि के कुलपति प्रो बंश गोंपाल सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. जी डी शर्मा ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि देश में पढ़ाई की पद्धति

अंग्रेजों के समय की चल रही है। इस पद्धति में बदलाव किया जाना चाहिए और भारतीय पद्धति से शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। भारतीय प्रणाली में भारत के सभी वेद शामिल हैं। इनके बारे में विद्यार्थियों को बताने पर विद्यार्थियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय प्रणाली में वेदों को काफी महत्व बताया गया है। आज बच्चे वेदों के बारे में जानते हैं लेकिन इसको व्यापक से बताए जाने की जरूरत है। इससे पढ़ाई में ईमानदारी और सत्वता आएगी।

यूजीसी भोपाल अध्यक्ष के डिप्टी डायरेक्टर एसएस बघेल ने कहा कि यूजीसी के पास विवि और महाविद्यालयों के लिए काफी फंड है, लेकिन संस्थान इसके लिए आवेदन नहीं करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने सभी संस्थाओं से फंड के लिए आवेदन देने की बात कहते हुए कहा कि फंड आने से संसाधनों का विकास होगा जिससे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार

भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / / का-2/प्र.अति.तह./2017

दिनांक दिनांक / / 2017

प्रति,

हल्का पटवारी

ग्राम कुरुद प.ह.न 14/19

तहसील काव्यवर्षा दुर्ग

विषय- बन्दोखस्त सुदृष्टकृष्ण के संबंध में विस्तृत जॉय प्रोटिकोले देने के बारे में।

सुदृष्टकृष्ण साकिन मरारपावा बोरोसी तह. बेरला के 0.813 हेक्टेयर अथवा 2000 वर्गफीट-185.87 वर्ग मी. (0.02 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता देवेन्द्रनाथ मिश्रा आ. रघुनाथ मिश्रा निवासी 115/7 जौ. टी. रोड बाली, हवाडी (प.बंगाल) के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 19.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

अति.तहसीलदार

भिलाईनगर जिला-दुर्ग

(मुहर)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार

भिलाई, जिला-दुर्ग

मामला क्रमांक / / 31/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवजी यादव आ. केदार यादव साकिन कुर्सीवार भिलाई तह. व. जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरुद प.ह.न 14/19 रा.नि.म.दुर्ग-1 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 490 रकबा 0.813 हेक्टेयर अथवा 2000 वर्गफीट-185.87 वर्ग मी. (0.02 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता देवेन्द्रनाथ मिश्रा आ. रघुनाथ मिश्रा निवासी 115/7 जौ. टी. रोड बाली, हवाडी (प.बंगाल) के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.6.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

अति.तहसीलदार

भिलाईनगर जिला-दुर्ग

(मुहर)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार

भिलाई, जिला-दुर्ग

मामला क्रमांक / / 31/6 सन् 2016-2017

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवजी यादव आ. केदार यादव साकिन कुर्सीवार भिलाई तह. व. जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम कुरुद प.ह.न 14/19 रा.नि.म.दुर्ग-1 तह. व. जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1572/222 का टु. रकबा 800 वर्गफीट-74.34 वर्ग मी. (0.006 हे.) हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सुभाष चंद्र खत्री आ. शांकरकिरण खत्री निवासी शांति नगर, सुपौला, भिलाई, के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 14.7.17 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर